

2



निकाय और
त्रिस्तरीय पंचायत
पुनाव एक साथ

3



महाविद्यालय
स्तर युवा
उत्सव

5



अविरल गंगा से
ही निर्मल गंगा
संभव

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 26

प्रति सोमवार, 4 नवंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कमजोर और गरीब कल्याण के लिये खोले विष्णुदेव साय सरकार ने खजाने जनकल्याण के लिये समर्पित मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने जनता के लिये शुरू की अनेकों योजनाएं

आमजन के कल्याण के लिये समर्पित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार एक के बाद एक जनहित से जुड़े फैसलों को लेकर जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली पानी, दाल-रोटी, मकान के बाद अब साय सरकार ने ऐसे बुजुर्गों का सहारा बनने की पहल की है जिनके परिवार में कोई नहीं है। परिवार के लोग बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं और बुजुर्गों को घर से दूर-दूर की ओर खदेते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों के लिये साय सरकार ने स्कारात्मक पहल करते हुए छत्तीसगढ़ वृद्ध पेंशन योजना को लागू करवा दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना को इंदिरा गांधी

वृद्ध पेंशन योजना भी कहा गया है जिस किसी वृद्ध पुरुष या महिला को उम्र 60 साल से ज्यादा है वही इसका आवेदन कर सकता है। योजना से मिलने वाले पेंशन राशि से वह अपना धरण-पोषण कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वृद्ध के परिवार की आय 02 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना से मिलने वाले राशि बुजुर्गों को उम्र के अनुसार दो भागों में बांटी गयी है जिनकी उम्र 60 से 79 होगी जिनमें सरकार 350 रुपये हर महीने पेंशन सरकार की और से दी जाएगी और जिन बुजुर्गों नागरिकों की उम्र 80 या उससे अधिक होगी सरकार हर महीने उन्हें 650 रुपये की पेंशन देगी। योजना में आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरना होगा।

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

राज्य



आसानी से जी सकेंगे अपनी जिंदगी

छत्तीसगढ़ वृद्ध पेंशन का यह उद्देश्य है कि जो देश के जितने भी बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं उन्हें राज्य सरकार आर्थिक रूप से मदद करने में उनकी सहायता करती है क्योंकि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं होता है या उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। और कई बार बुढ़ापे में इनके परिवार वाले इन लोगों को घर से निकाल देते हैं। इसी को देखते ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसके जरिये वह इन लोगों को आत्मनिर्भर बना सकता है और यह आसानी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। राज्य के ऐसे कई लोग बुजुर्ग नागरिक जो अपनी आर्थिक रूप से कमजोर है जो कि उन्हें सरकार द्वारा मदद के रूप में पेंशन प्रदान कर सकते हैं। सरकार बुजुर्गों के हित के लिए कई सारी योजनाओं को जारी करते रहते हैं। (शेष पेज 2 पर)

क्या अनुभवी नेताओं के बजाय संख्या बल पर भरोसा जताने वाले पटवारी को मिलेगी उपचुनाव में सफलता?

लोकसभा में 29-0 से हारने वाले कप्तान की क्या अधिकच्छी-अधपक्की टीम शायद रहेगी भविष्य में फेल?

-विजया पाठक

लगभग दस माह पूर्व कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की कमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथ में सौंपी थी फिलहाल वह उम्मीद कहीं से कहीं तक पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। कभी पार्टी नेताओं में आपसी खींचतान तो कभी मनभेद और मतभेद में ही पार्टी ने अपने बेशकीमती दस माह बिता दिये। अब जब प्रदेश के दो प्रमुख जिलों में उपचुनाव की बारी आई तो आनन फानन में प्रदेश अध्यक्ष



विजया

सीनियर को जूनियर और जूनियर को पद देकर अपनी पशासनिक अक्षमता साबित कर रहे हैं जीतू पटवारी

क्या मध्यप्रदेश में जीतू राज के साथ कांग्रेस का पतन चालू होगा विधानसभा उपचुनाव में हार के साथ?

जीतू पटवारी ने एक ऐसी फौज तैयार कर दी जिससे क्या काम करना है यह बात न तो पटवारी को समझ आ रही है और न ही फौज के सदस्यों को। वहां फौज से आशय प्रदेश कार्यकारिणी समिति में शामिल हुए 150 से अधिक उन कार्यकर्ताओं और विधायकों से है जिन्हें पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया है। इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यकारिणी

के निर्माण के पीछे पार्टी का क्या उद्देश्य है यह तो समझ से परे है। लेकिन एक बात तो तय है कि इतनी बड़ी फौज लेकर कोई भी नेता पार्टी का समन्वय बेहतर ढंग से चलाने में सक्षम होगा यह दमखम फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं में तो दिखाई नहीं दे रहा। जबकि कमलनाथ के पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई थी। (शेष पेज 6 पर)

कांग्रेस के सच्चे सिपाही का सबूत दे रहे कमलनाथ

डॉ. अभिषेक सिंघई और डॉ. रश्मि वर्मा 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्डियोडायबिटोलॉजी में सम्मानित

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान ने अकादमिक उत्कृष्टता, नवाचार और साझाकरण की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। प्रो. सिंह ने एम्स भोपाल में कई अकादमिक उपलब्धियों के पीछे एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया है, जो स्वास्थ्य देखभाल में शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संकाय और छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

एल ही में मेडिसिन विभाग के डॉ. अभिषेक सिंघई और ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की डॉ. रश्मि वर्मा को प्रतिष्ठित कार्डियोमेटाबोलिक मेडिसिन (FCCM) फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान हाल ही में भोपाल में आयोजित 22वीं नेशनल

कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्डियोडायबिटोलॉजी के दौरान दिया गया। यह विशिष्ट पुरस्कार डॉ. सिंघई और डॉ. वर्मा के पिछले दशक में कार्डियोमेटाबोलिक मेडिसिन के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। उनके शोध और चिकित्सीय कार्यों ने कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों की समझ और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रो. सिंह ने डॉ. सिंघई और डॉ. वर्मा को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी और उन्हें उत्कृष्टता की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, आपकी समर्पण और मेहनत ने न केवल आपको सम्मानित किया है बल्कि एम्स भोपाल की प्रतिष्ठा को भी कार्डियोमेटाबोलिक मेडिसिन के क्षेत्र में ऊंचा किया है। (जगत फीचर्स)



बडेरिया तिगड्डा से बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी के बडेरिया तिगड्डा से एक पत्रकार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की घटना करीब दोपहर 1 बजकर 30 मिनट के आसपास की है। सीसीटीवी फुटेज में उक्त घटना कैद हो गई है, जिसमें चोर को मोटरसाइकिल को उठाते हुए देखा जा सकता है। पत्रकार अमित राजपूत की प्लेटेना काले रंग की जिसका नम्बर एम पी 15 एमपी 4001 है। जो की बडेरिया तिगड्डा स्थित प्रवीण पाठक के घर के सामने रखी थी। पत्रकार ने

बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोरी की घटना दिनदहाड़े हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों ने बताया कि इसके पहले भी आशीष दुबे पत्रकार की चार पहिया वाहन घर के सामने से एवं शहर जैन मंदिर के पास से मोटर साइकिल चोरी हो गई है। पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और चोर को गिरफ्तार करें। (जगत फीचर्स)

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सर्च पर निकले सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया 5 किलो का IED, मौके पर किया डिफ्यूज़

-संवाददाता

जगत प्रवाह. बीजापुर। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के नापाक मनसूबे को नाकाम कर दिया। दरअसल, यहां नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के

उद्देश्य से 5 किलो का IED बम प्रेशर स्विच सिस्टम से प्लॉट किया था, लेकिन सर्च पर निकले जवानों की सतर्कता और सूझबूझ से IED बरामद करते हुए सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया गया। IED को निष्क्रिय करने का एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक,

DRG बीजापुर, CoBRA 202 और BDS बीजापुर की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन और डिमाईनिंग के लिए सावनार से कोरचोली की ओर निकली थी, तब डी-माईनिंग के दौरान बीडीएस बीजापुर की टीम ने यह IED बरामद किया। (जगत फीचर्स)

महाविद्यालय स्तर युवा उत्सव



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी में महाविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया गया। यह युवा उत्सव तीन दिनों तक चलेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधाओं जैसे रंगोली, चित्रकला, परिचर्चा, वाद-विवाद प्रश्न मंच, बले मॉडलिंग, कार्टूनिंग एवं समूह गायन, समूह

नृत्य, एकांकी, मुकाभिनय, स्किट, मिमिक्री आदि विधाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती पूजन एवं माल्यार्पण से किया गया इसके बाद महाविद्यालय युवा उत्सव प्रभारी श्रीमती सुरभि चौरा द्वारा युवा उत्सव की संपूर्ण रूप रेखा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. जे के जैन द्वारा की गई। रंगोली, कार्टूनिंग

एवं परिचर्चा विधाओं का आयोजन किया गया। डॉ. सुनील कुमार बीरासी एवं डॉ. सादिया पटेल एवं डॉ. संजय कुमार पटवा द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया एवं विभिन्न विधाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा कार्यक्रम का संचालन सुनित काशिय के द्वारा किया गया। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

कनाडा भारत पर आरोप लगाने में बिना ठोस सबूत के आगे बढ़ रहा है

कनाडा की जस्टिन टूडो सरकार के रवैये को देखते हुए यह साफ है कि वह दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने या इन्हें दोबारा पटरी पर लाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जिस तरह से बिना कोई ठोस सबूत मुहैया कराए वह भारत पर लगाए अपने आरोपों का दायरा बढ़ाती जा रही है, उसे द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी की किसी भी भावना से जोड़ना मुश्किल है। यह काफी हद तक साफ तभी हो गया था जब पिछले साल महज सूचनाओं के आधार पर जस्टिन टूडो ने अपने देश की संसद में यह आरोप लगा दिया था कि वहां हुई एक खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। तब भी भारत ने यही कहा था कि उनके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो मुहैया कराए, मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन उधर से कोई सबूत नहीं दिए गए। हुआ यह कि पिछले दिनों खुद टूडो को एक समिति के सामने कबूल करना पड़ा कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे।

दिलचस्प है कि इस सार्वजनिक शर्मिंदगी के बाद भी उनकी सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी तक कोई सबूत नहीं दे पा रही है, लेकिन अलग-अलग तरीकों से आरोपों का दायरा बढ़ाती जा रही। पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को 'पर्सन ऑफ इंटररेस्ट' घोषित कर दिया और फिर अमेरिकी

अखबार 'वॉशिंगटन पोस्ट' में स्टोरी प्लांट करवाई कि इस हत्या के पीछे भारत के गृहमंत्री का हाथ है। ऐसे में स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि अखिर कनाडा की जस्टिन टूडो सरकार इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तय मानकों में कहीं से फिट नहीं बैठती। घटनाओं और हालात के जरिए इसे समझने की कोशिश करें तो

यह जाहिर हो जाता है कि वह घरेलू राजनीतिक दबावों और चुनावी फायदों से निर्देशित हो रही है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मानक और द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी कम से कम फिलहाल उसकी प्राथमिकता में नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इस स्थिति का प्रभाव न सिर्फ दोनों के रिश्तों पर बल्कि कनाडा में रह रहे या वहां पढ़ाई के लिए जाने की सोच रहे छात्रों और युवाओं पर पड़ रहा है। इन पहलुओं को देखते हुए

ही इन हालात में भी भारत ने यह दोहराया है कि द्विपक्षीय रिश्तों के संदर्भ में आज भी उसकी मुख्य चिंता उन खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां ही हैं जिन्हें अभिषेकित की आजादी के नाम पर बेलगाम छोड़ दिया गया है। देखा होगा कि कब कनाडा में अंदरूनी राजनीति के समीकरण बदलते हैं या कब वहां की सरकार अंतरराष्ट्रीय मामलों को घरेलू राजनीति के दबावों से अलग रखने का अनुशासन दिखा पाती है।



सियासी गहमागहमी

मंत्री जी गाय पालन की बना रहे योजना



पिछले दिनों राज्य सरकार ने गौवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में किया। इस कार्यक्रम में राज्य के कई कैबिनेट मंत्री थे। जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंच से गौशाला निर्माण और गौ-पालन से जुड़ी योजनाएं गिनवा रहे थे तब पास में ही बैठे एक कैबिनेट स्तर

के मंत्री ने पास बैठे दूसरे विधायक सदस्य से कान में गाय पालने की इच्छा प्रकट कर दी। शायद मंत्री जी गौ सेवा का यह कार्य शासकीय योजना का लाभ लेने के लिये उठाने की बात कर रहे थे। बता दें आपको की मंत्री जी इंदौर संभाग से हैं और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मंत्री जी सही में गाय पालन का कार्य कर गौ-सेवा करना चाहते हैं या फिर शासकीय योजना का लाभ लेकर अपने खजाने को पूरा करना चाहते हैं।

मुख्य सचिव की फटकार से सहमे हुए हैं अधिकारी



बीते दिनों उमरिया जिले के बांधवगढ़ में हुई 10 हाथियों की मौत की घटना ने सभी अफसरों को सख्ते में डाल दिया है। वन विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अफसर ने पहले तो हाथियों की मौत की घटना को सामान्य घटना समझ नजर अंदाज किया।

लेकिन जब शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक ली और बैठक में अधिकारीगण से मुख्य सचिव महोदय ने ऑनलाइन माध्यम से ही हाथियों की मृत्यु का कारण पूछा तो अधिकारी गण बगले झांके लगे। यह देख मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मुख्यमंत्री के सामने ही वन विभाग के आला अफसर को फटकार लगाई। अब जब मुख्यमंत्री ने दो वन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया तो संबंधित अधिकारी गण मुख्य सचिव के सामने जाने से बच रहे हैं यह सोचकर की कहीं अगली आंच उन पर न पड़ जाये।

हफते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

INDIA की 5 गारंटी हर वर्ग के लिए न्याय और तरक्की सुनिश्चित करेगी - ये प्रगतिशील और समावेशी कदम गरीब, मध्यम वर्ग, बहुजनों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारों की समृद्धि तय करेगे।

भाजपा ने महाराष्ट्र के लोगों से उनकी पूर्ण सरकार, उनके हक के रोजगार, रोजगार बनाने वाले व्यापार, उनकी जमीन और बचत तक चोरी कर ली।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु को करीब एक हफ्ता बीत चुका है लेकिन दोषियों को पकड़ना तो दूर मध्य प्रदेश सरकार अब तक हाथियों की मृत्यु के कारण को भी स्पष्ट नहीं कर सकी है।



यह अत्यंत घिंता का विषय है।

-कमलनाथ

प्रेम कांठेस 38238

@OfficeOfK.Nath

राजवीरों की बात

फैशन की दुनिया से संसद भवन की सीढ़ियाँ तक का सफर तय कर चुकी हैं मेनका गांधी

समता पाठक/जगत प्रवाह



दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी मेनका गांधी की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई लॉर्स स्कूल से हुई. फिर उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से प्रेज्युएशन की और जेएनयू भी गई. मेनका ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और यहाँ उनकी गांधी फैमिली में एंट्री की वजह बना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीर देखी तो पहली नजर में उनपर फिदा हो गए। संजय गांधी और मेनका की मुलाकात हुई। दोनों करीब आए और जुलाई 1974 में एंगेजमेंट कर ली। दो महीने बाद सितंबर 1974 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। संजय गांधी और मेनका का साथ करीब 6 साल का रहा। जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। संजय के जाने से इंदिरा गांधी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने संजय की जगाह लेने के लिए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे किया। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका गांधी को उनका वारिस मान रहे थे। खुद मेनका को भी लगा था कि अपने पति की विरासत की असली हकदार वही है।

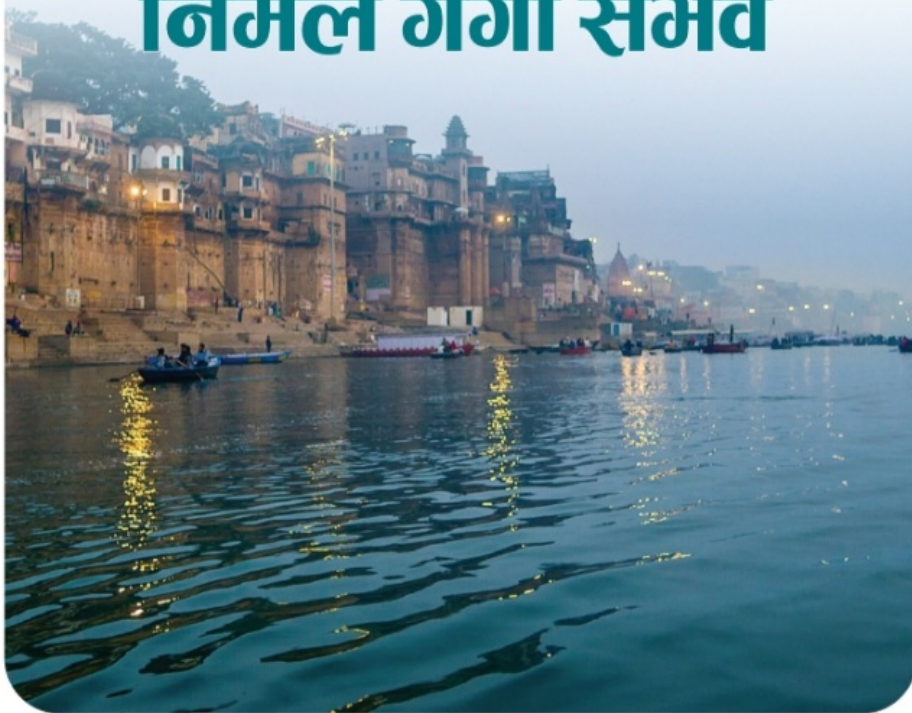
संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के पीछे खड़े थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंडी भी शामिल थे। मार्च 1982 में डंडी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया। जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से इस सभा का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना और यह जताना था कि संजय की विरासत की हकदार मेनका गांधी ही हैं। मेनका बाकायदे इस सभा में आने का न्योता भेजा गया।

स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब 'द रेड साठी' में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी कोई डंडी की उस सभा की भनक लग गई। ठीक उसी समय उन्हें लंदन जाना था। इंदिरा ने बहू मेनका को बुलाकर लखनऊ की सभा में न जाने की सख्त नसीहत दी। हालांकि मेनका ने उनकी बात नहीं मानी। सभा में गईं और वहाँ धारदार भाषण दिया। इंदिरा भारत लौटतीं तो उन्हें मेनका के सभा में जाने का पता चला। वह आग बबूला हो गईं। उन्हें लग रहा था कि मेनका ने उनका अपमान किया है। इंदिरा ने पहले अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी। जिसमें यह भी लिखा कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि संजय गांधी और उनकी शादी हो।

जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं कि लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफरदरवाजे वाले मकान में पहुँचीं तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास से नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने तल्ल्खी से कहा- बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि आपको मैडम बुला रही हैं। मेनका गांधी जब नीचे आईं तो वहाँ इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव आरके धवन भी मौजूद थे।

मोरो लिखते हैं कि इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फोन किया। अंबिका के जरिए मेनका और उनकी सास के बीच लड़ाई की खबर मीडिया तक पहुँच गई। रात 9 बजते-बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। रात 9:30 बजे के करीब मेनका की बहन अंबिका भी वहाँ पहुँचीं। वह अपनी बहन से बात कर रही थीं कि इंदिरा फिर कमरे में आईं और दोबारा घर से निकलने को कहा। इस बार अंबिका ने उनकी बात काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, यह घर उसका भी है। इंदिरा गांधी ने गुस्से में जवाब दिया- तौत, यह घर भारत के प्रधानमंत्री का है।

अविरल गंगा से ही निर्मल गंगा संभव



जगत प्रवाह. गोपाल। भारत की सबसे



पर्यावरण की फिक्र डॉ. प्रशांत सिन्हा पर्यावरणविद्

महत्वपूर्ण नदी गंगा है। यह नदी उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू-भाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक सम्पदा ही नहीं जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किमी तक आस्था तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। पतित पावनी गंगा की निर्मलता तथा अविश्रलता से जैव विविधता समृद्धि होगी। आज भारत की सबसे पूजनीय नदी गंगा को सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और अन्य कारणों से "अविरल और निर्मल" बने रहने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक नदी तभी संपूर्ण होती है, जब यह समस्त घाटी क्षेत्र से, सभी मौसमों में एक अविरल धारा की तरह बहती रहे और उसमें एक भौगोलिक इकाई और पर्यावरणीय इकाई का गुण हो। निर्मल धारा का मतलब है बिना किसी प्रदूषण का बहना। अविरल धारा का मतलब होगा कि बिना किसी बाधा या रुकावट के बहना, यानी नदी लगातार बहती रहे। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि नदी में या सागर में बिना किसी

बाधा के मिल सके।

अविरल गंगा से ही निर्मल गंगा संभव" यह कथन न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। गंगा, जिसे हम नदियों की माँ कहते हैं, भारतीय सभ्यता की धारा है। इतिहास के पन्नों में, वेदों की ऋचाओं में और अतीत की गौरवगाथाओं में, गंगा का निरंतर प्रवाह जीवन का प्रतीक रहा है। लेकिन आज, हमारी यह प्राचीन धरोहर प्रदूषण, अतिक्रमण और उपेक्षा की मार झेल रही है। गंगा का निर्मल प्रवाह तभी संभव है जब वह अविरल बह सके। जब हम गंगा की बात करते हैं तो वह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण इकोसिस्टम की बात होती है। इसके तटों पर करोड़ों लोग रहते हैं, इसकी मिट्टी में न जाने कितने जीव-जन्तु, पेड़-पौधे और जलचर अपना घर बनाए हुए हैं। गंगा की अविरलता में जीवन के अनेक पहलू जुड़े हुए हैं। यह नदी न केवल जलधारा का संकलन करती है, बल्कि हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक ताने-बाने को भी अपने साथ जोड़कर बहती है। यह समझना जरूरी है कि गंगा की अविरलता केवल जल प्रबंधन से संभव नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता और हमारी सोच में बदलाव आवश्यक है। आज गंगा को बहने में जितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, वे मानव-निर्मित हैं। उद्योगों के प्रदूषण से लेकर गंगा के किनारों पर फैलते शहरीकरण तक, यह सब मिलकर गंगा की जीवनधारा को बाधित कर

रहे हैं। क्या यह सही नहीं होगा कि हम अपने उपभोग और विकास की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करें? देखा जाए तो सरकारें 1985 से ही गंगा को स्वच्छ करने के लिए प्रयासरत है लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आज भी दशा वैसी ही बनी हुई है। हमारी संस्कृति में गंगा को देवी का स्थान दिया गया है। जिस गंगा को हमने देवी मानकर पूजा है, उसी गंगा को हमने जल-मल और अपशिष्ट का स्रोत बना दिया है। गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की, बल्कि हर व्यक्ति की है जो इस धरती पर रहता है। हमें यह समझना होगा कि गंगा की अविरल धारा तभी बनी रहेगी जब हम उसे सम्मान देंगे। ऊँचे ऊँचे बांध बनाकर उसकी अविरलता को खत्म कर दिया गया और जब अविरलता नहीं होगी तो निर्मलता कैसे होगी? हम गंगा को खतरनाक स्तर पर ला चुके हैं। सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए बांध बना दिए गए हैं, पानी को मनचाही दिशा में ले जाने के लिए बैराज बना दिए गए हैं। वनों की कटाई और खनन आदि ने गंगा के जलबहाव क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया है। आज जरूरत है कि हम गंगा की अविरलता के साथ-साथ उसकी निर्मलता की बात करें। सरकारी योजनाओं से लेकर स्थानीय जागरूकता अभियानों तक, हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जल-प्रदूषण से मुक्त गंगा के बिना यह मुमकिन नहीं कि वह अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप में जीवित रह सके।

(जगत फीचर्स)

हाथी और मानव के बीच बढ़ा संघर्ष



-प्रमोद भार्गव

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों से हाथियों की असामयिक मौत की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। नई बात इन हाथियों के मौत के कारण से जुड़ी है। इस बार एक सप्ताह के अंतराल में दस हाथियों की मौत हुई है और इस मौत का ठीकरा वनाधिकारियों ने संक्रमित कोदो-कुटकी की खेतों को खाने पर पड़े दिया।

अक्सर देखने में आया है कि उमरिया जिले के इस उद्यान में जब भी हाथी या बाघों की मौत होती है तो हाथियों की मौत को जहर खिलाना और बाघों की मौत को आपसी संघर्ष में भरना बताकर वन विभाग अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। इन मौतों के बाद हाथियों का गुस्सा उद्यान से 10 किमी दूर देवरा के ग्रामीणों पर टूटता दिखा। 13 हाथियों के इस झुंड से तीन हाथी अलग हो गए थे। इन हाथियों में से एक ने देवरा, ब्राहे और बांका ग्राम में पहुंचकर तीन लोगों पर हमला बोला। इनमें से दो की मौत हो गई और एक घायल है। इस मर्दांग हाथी को वनकर्मियों ने पकड़ लिया है। वनाधिकारी बता रहे हैं कि यह हाथी उन्माद (मुस्थ) की अवस्था में पकड़ है। इस अवस्था का मतलब होता है कि हाथी प्रजनन काल से गुजर रहा है। इस अवधि में इसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है और यह आक्रामक हो जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दस हाथियों के मामले को गंभीरता से लिया और निगरानी में लापरवाही के बताने के चलते आचार्यराज्य के निदेशक गौरव चौधरी और प्रभारी सहायक वन संरक्षक अधिकारी फतेह सिंह को निर्लक्षित कर दिया।

14 सदस्यीय चिकित्सकों के एक दल ने हाथियों के शव-विच्छेदन में पाया कि हाथियों के पेट में संक्रमित कोदो-कुटकी पाया गया है। इसे हाथियों ने जंगल से स्टे

खेतों में खड़ी कोदो-कुटकी की फसल को खाया था। यह कोदो-कुटकी माइकोटोक्सिन (कवक विषा) बन गया था। बारिश के बाद प्रतिकूल मौसम के चलते कोदो-कुटकी सहित कवक विषा उत्पन्न हो जाता है। अतएव संक्रमित फसल के सेवन से पशुओं में संक्रमण हो जाता है। इस संक्रमण का समय रहते इलाज न हो पाए और यह बढ़ता जाए तो प्राणी की मौत हो जाती है। यह मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। अब वन-विभाग ने उद्यान की सीमा से स्टे खेतों की फसल नष्ट करा दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसी आशंका थी तो हाथियों को इन खेतों की फसल को चरने ही क्यों दिया? जबकि वर्तमान में प्रत्येक बड़े हाथी, बाघ एवं चीता के आरक्षित आवासिय वनों में कई-कई पशु-चिकित्सक तैनात हैं और निगरानी के लिए अनेक वन रक्षक तैनात रहते हैं। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के पहले कोदो खाने से हाथियों की मौतें हुईं हों, ऐसी खबर नहीं आई? क्या हाथियों ने पहली बार यह फसल खाई थी? हालांकि संक्रमित भोजन के नमूने दोष की अन्य प्रयोगशालाओं में भेजने के साथ सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रयोगशाला हैदराबाद से भी परामर्श लिया जा रहा है। एएसआईटी और एसटीएसएफ के दल भी सभी संभावित पहलुओं पर जांच करेंगे।

भारत सरकार ने हाथी को दुर्लभ प्राणी व राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा दी हुई है। इसलिए जंगलों में हाथियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में हाथी सह-जीवन का हिस्सा है। इसीलिए हाथी पाले और पूजे जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी लकड़ी बुलाई का काम करते हैं। सर्कस के खिलाड़ी और सड़कों पर तमाशा दिखाने वाले मंदायी इन्हें पढ़ा व सिखाकर अजूबे दिखाने का काम भी करते रहे हैं। साधु-संत और सेनाओं ने भी हाथियों का खूब उपयोग किया है। कई उद्यानों में पर्यटकों को हाथी की पीठ पर बिठाकर बाघ के दर्शन कराए जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद अब ये केवल प्राणी उद्यानों

और विडियाघरों में ही सिमट गए हैं। बावजूद इन उद्यानों में इसकी हड्डियाँ और दांतों के लिए खूब शिकार हो रहा है। हाथी के शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन व्यवहार में हाथी का शिकार करने वालों से लेकर आम लोग भी इस तरह के कानूनों की परवाह नहीं करते? कर्नाटक के जंगलों में कुख्यात तस्कर वीरपन ने इसके दांतों की तस्करी के लिए सैकड़ों हाथियों को मारा था। चीन हाथी दांत का सबसे बड़ा खरीददार है। जिन जंगलों के बीच में रेल पटरियाँ बिछी हैं, वहाँ ये रेलों की चपेट में आकर भी बड़ी संख्या में प्राण गंवाते रहते हैं।

मनुष्य के जंगली व्यवहार के विपरीत हाथियों का भी मनुष्य के प्रति क्रूर आचरण देखने में आता है। जैसा कि 10 हाथियों की मौत के बाद इसी झुंड के एक हाथी ने तीन ग्रामीणों पर जानलेवा हमला बोला है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और कर्नाटक के जंगली हाथी अक्सर जंगल से भटककर ग्रामीण इलाकों में उतपात मचाते रहते हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में हाथियों ने इतना भयानक उतपात मचाया था कि यहाँ 22 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। कर्नाटक और बिहार में इन हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या जोड़ लें तो ये हाथी दस-बारह साल के भीतर करीब सवा-सी लोगों की जान ले चुके हैं। शहडोल, रायगढ़, सरगुजा जिलों के दूर-दराज के गाँवों में रहने वाले आदिवासियों के घरों में उतारी जाने वाली शराब को पीने की तड़प में भी हाथी गंध के सहारे आदिवासियों की झोपड़ियों को तोड़ते हुए घुसते चले जाते हैं और जो भी सामने आता है उसे सूंड से पकड़ कर पटका और पेट पर भारी-भरकम पैर रख उसकी जीवण लीला खत्म कर देते हैं। इस तरह से इन मर्दांग हाथियों द्वारा हत्या का सिलसिला हर साल अनेक गाँवों में देखने में आता रहता है।

पालतू हाथी भी कई बार गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्से में क्यों आते हैं, इसे समझने के लिए इनके आचार, व्यवहार और प्रजनन संबंधी क्रियाओं व भावनाओं को समझना जरूरी है। हाथी मद की अवस्था में आने के बाद ही मर्दांग होकर अपना आपा खोता है। हाथियों की इस मनस्थिति के सिलसिले में प्रसिद्ध वन्य प्राणी विशेषज्ञ

रमेशा बेदी ने लिखा है कि जब हाथी प्रजनन की अवस्था में आता है तो वह समागम के लिए मादा को ढूँढता है। ऐसी अवस्था में पालतू नर हाथियों को लोगों के बीच नहीं ले जाना चाहिए। मद में आने से पूर्व हाथी संकेत भी देते हैं। हाथियों की आँखों से तेल जैसे तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है और उनके पैर पेशाब से भीले रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में महावतों को चाहिए कि वे हाथियों को भीड़ वाले इलाके से दूर बंदी अवस्था में ही रखें, क्योंकि अन्य मादा प्राणियों की तरह रजस्वला स्त्रियों से एस्ट्रोजन हार्मोन की महक उठती है और हाथी ऐसे में बेकाबू होकर उन्मादित हो उठते हैं। त्रिचूर, मैसूर और वाराणसी में ऐसे हालातों के चलते अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं। ये प्राणी मनोविज्ञान को ऐसी ही मनःस्थितियों से उपजी घटनाएँ हैं। वैसे हाथियों के ऐसे व्यवहार को लेकर काफी नामसमीची की स्थिति है, मगर समझदारी इसी में है कि धन के लालच में मद में आए हाथी को किसी उत्सव या समारोह में न ले जाया जाए। जिस हाथी ने तीन लोगों पर हमला बोला है, वह उन्माद की अवस्था में ही था।

उत्पाती हाथियों को पकड़कर बीस साल पहले मध्यप्रदेश में 'ऑपरेशन खेदा' चलाया गया था। हालांकि पूर्ण वयस्क हो चुके हाथियों को पालतू बनाना एक चुनौती व जोखिम भरा काम है। हाथियों की बाल्यावस्था में ही आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। हाथी उन्माद में भले ही सीधा और भौला लगे पर आदमी की जान के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी हैं, उनमें एक हाथी है और दूसरा है भालू है। हाथी उत्तेजित हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता है। फिलहाल इस तरह हाथी को पालतू बनाए जाने के उपाय बंद हैं। आखिर, जिस वन अमले पर अरबों रुपए का बजट सालभर में खर्च होता है, उसके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय क्यों नहीं है? अतएव हाथियों की मौत हो या वे उन्माद मचाएँ, मरना ग्रामीणों का ही होता है। इस मामले में भी सीधे-सीधे मरना ग्रामीणों की फसलें उजाड़ दी गईं। जबकि सावधानी नहीं बताने के लिए किसी पशु-चिकित्सक, वनाधिकारी या वन रक्षक को दोषी नहीं ठहराया गया? (जगत फीचर्स)

क्या अनुभवी नेताओं के बजाय संख्या बल पर भरोसा जताने वाले पटवारी को मिलेगी उपचुनाव में सफलता?

(पेज 1 का शेष)

उस समय ऐसा माहौल नहीं बना था। किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं था। एक सप्ताह हुई कार्यकारिणी बनाई गई थी जिसमें समरूपता का समावेश था। क्योंकि हम मानते हैं कि कमलनाथ एक अनुभवी राजनेता है। उन्हें पता होता है कि किस नेता को किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी है जिससे पार्टी का फल हो सके।

युद्ध संख्या बल से नहीं बुद्धिमानी से जीता जाता है

कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी को यह बात समझ लेना चाहिए कि कोई भी युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से जीता जाता है। भले ही आज पटवारी के कहने पर पार्टी आलाकमान ने सभी नाराज नेताओं को संतुष्ट करने के लिये प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दे दिया हो, लेकिन इच्छुक तो यह है कि अगर यह सब नये कार्यकारिणी का सदस्य होने के कारण रोज भोपाल आते जाते रहें और शैरीन स्तर पर काम कैसे होगा। जनता के बीच तक नेता और कार्यकर्ता कैसे पहुंचेंगे। और अगर मैदानी स्तर तक नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंचें तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब पार्टी को बड़ नुकसान हो सकता है।

अनुभवी नेताओं को मिलना था स्थान

प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भले ही पार्टी आलाकमान ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेताओं को स्थान दिया है, लेकिन देखा जाये तो पार्टी को वहीं कार्यकारिणी को दोबारा से कार्य करने का अवसर देना चाहिए था जो पूर्व में कमलनाथ के समय में थी। यह वही कार्यकारिणी के सदस्य थे जिन्होंने राज्य में कांग्रेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना परिश्रम लाया था। यही नहीं इन्हीं सदस्यों के बल बूते पर पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा किया और चुनाव में पूरे दायख के साथ उतरे थे। लेकिन अब पार्टी ने ऐसे विधायकों की फौज तैयार करके मैदान में खड़ी कर दी है जिनके बीच समन्वय करने में ही प्रदेश अस्थिर जीतू पटवारी का समय निकल जायेगा और पार्टी को भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

विवेकानंद जी का कथन आता है याद

प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या को देखकर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का कथन याद आता है वह कहते थे कि मुझे समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो लोगों की भीड़ नहीं बल्कि फुटबॉल टीम के जितने 11 खिलाड़ी की काफी है। यही बात कमलनाथ के समय तैयार हुई कार्यकारिणी पर क्लिकलु सटीक बैठती है जहां उन्होंने गिनती के लोगों को अपने टीम में स्थान दिया और सभी ने कड़ी मेहनत, परिश्रम और योग्यता के बल पर कांग्रेस पार्टी को मध्यप्रदेश में नया मुकाम दिया था।

वया उपचुनाव जिता पाने में सफल होगी कार्यकारिणी?

जिस हिस्सा से पार्टी आलाकमान ने पटवारी के कहने पर कार्यकारिणी की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है उसे देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या यह सभी सदस्य बुद्धि और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव को जिता पाने में सफल होंगे। मुझे तो कार्यकारिणी के सदस्यों की उदारमनता देखकर प्रतीत होता है कि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आगामी समय में होने वाले अन्य चुनावों में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या पर एक बार पुनः विचार करें और नये स्तर से कार्यकारिणी तैयार कर अनुभवी नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपने की पहल करें।

अनुभवी कमलनाथ उठाते हैं जनता से जुड़े मुद्दे

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भले ही पिछले 10 महीनों से प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन जनता के दिलों में वे आज भी बसते हैं। छिंटवाड़ा भले ही उनसे भाजपा ने छल-बल से छीन लिया हो, लेकिन छिंटवाड़ा की जनता आज भी उन्हें अपना भगवान मानती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। यही कारण है कि समय मिलते ही कमलनाथ सीधे छिंटवाड़ा पहुंचते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को हल करने का काम करते हैं। पिछले दिनों कमलनाथ ने अपने का टवीट में लिखा कि लाइली बहना योजना में नए

हितग्राही नहीं जोड़े जा रहे। लाइली बहना योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ने का श्रेयोपूर जिले की विजयपुर विधानसभा काम शून्य है, पुराने हितग्राहियों की छटनी तेजी से जारी है। जनता को मिलने वाली विभिन्न-विधायी सहायताओं को रोककर केवल एक उपाय में राशि जमा करनी बनाना भीलौली जनता से इस शक्ति सरकार की बजाय ठगी है। परिवार के हर सदस्य की जेब काटना और फिर लूट के उसी का एक छटा सा हिस्सा जनता को लौटाकर वाहवाही लूटना इस सरकार की आदत बन चुकी है।

कमलनाथ कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर काम कर रहे हैं

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भले ही कोई प्रमुख भूमिका में न हों लेकिन आज वो कांग्रेस के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पद और लालसा के बगैरे सच्चे मन से पार्टी का हित चाह रहे हैं। एक अच्छे राजनेता का परिचय देते हुए किसी भी प्रकार का विवादस्पद बयान नहीं देते हैं। जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। जो कोई भी बयान देते हैं वह बहूत ही सटीक और सारापिठ होते हैं। यही वजह है कि सरकार और पार्टी में उनके बयानों का काफी तबज्जो दी जाती है। खुद सरकार भी उनके बयानों से सक्ते में आ जाती है। कमलनाथ की शैली की विपक्षी पार्टी भी तारीफ करती है। मैं जानती हूँ कि बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो कमलनाथ की तारीफ करते हैं। यदि कांग्रेस को प्रदेश में आगे बढ़ना है तो कमलनाथ जैसे नेताओं की बहुत जरूरत है जो खुद की नहीं बल्कि पार्टी का हित चाहते हैं।

लक्ष्मण सिंह ने नई कार्यकारिणी पर उठाए सवाल

मध्यप्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने जीतू पटवारी को टीम पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कमरे में बैठकर कार्यकारिणी बनाई गई है इसमें कई कार्यकर्ताओं को इसमें जगह नहीं दी गई है। आपको बता दें कि नई प्रदेश कार्यकारिणी में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कार्यकारिणी का विरोध किया है। इंदौर के एक नेता ने जिला

आबादी के आंकड़ों की छिपी कहानी



-रघु ठाकुर

पिछले कुछ दिनों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे लगता है कि देश में आबादी वृद्धि स्वयं मेव नियंत्रित हो चुकी है और अब आबादी

वृद्धि कोई समस्या नहीं है। यह बात हमारे देश के बौद्धिक तत्वों में भी चल रही है जो इन अध्ययन संस्थाओं के अध्ययनों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वे यह पता लगाने का प्रयास नहीं करते हैं कि इन अध्ययनकर्ताओं ने किस माध्यम से अध्ययन किए हैं और कब किए हैं और क्या वास्तव में जमीन पर ऐसी स्थिति है? जिसकी चर्चा वह कर रहे हैं। अक्सर यह होता है कि देश के विभिन्न तबके अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उनकी तथ्यात्मक जांच करायें और आंकड़े उद्धृत, प्रचारित और प्रसारित करने लगते हैं। भारतीय राजनीति के राजनीतिक समूह भी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को अपनी अपनी राजनीतिक आवश्यकता और सुविधा के अनुसार प्रचारित करते हैं और कई बार तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन अध्ययन रिपोर्टों को अपना आधार बताते हैं। लगभग दो तीन दशक पहले गोपाल सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने यह कहा था कि देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि तुलनात्मक रूप से गैर मुस्लिम या हिंदू आबादी की वृद्धि दर से कम है और इस रिपोर्ट का काफी सार्वजनिक प्रयोग देश के गैर भाजपाईं समूहों याने कांग्रेस, समाजवादी, मार्क्सवादी दलों ने किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अध्ययनकर्ताओं की रिपोर्ट भी आई कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तथा तुलनात्मक रूप से हिंदू आबादी घट रही है। इस समूह ने अपने अध्ययनकर्ताओं की रिपोर्ट को जोरशोर से प्रसारित किया और आम हिंदू मानस में यह प्रचारित करने का प्रयास किया की बहुत जल्दी देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यहां तक की इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक स्वर्गीय पी सुदर्शन ने तो यह सार्वजनिक बयान दिया था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ और मेरी जानकारी में कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है कि जिसमें यह तत्व सामने आया हो कि स्वर्गीय सुदर्शन की अपील पर कितने हिंदुओं ने ज्यादा बच्चे पैदा किए या किसी अन्य ने इस पर भी विश्वासनीय रिपोर्ट नहीं आई कि मुस्लिम भाइयों के स्व नियंत्रण से आबादी की वृद्धि में कितनी कमी आई या नियंत्रण हो सका।

हालांकि इन दोनों घटनाओं का यह तो असर हुआ कि परिवार नियोजन की योजनाएं और विभागात्मक प्रयास हो गए। जैसे भी 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में, आपातकाल के दिनों में, परिवार नियोजन के नाम पर इंडो-ज्यादातियों ने एक अहम भूमिका निभाई और एक मुस्लिम मतदाता के हिस्से ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी और कांग्रेस के लिए वोट नहीं दिया था। उस समय के समाचार पत्रों में यह सूचनाओं आई थी कि स्वर्गीय संजय गांधी परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सरकार की शक्ति से लागू करने के पक्षधर थे और इसीलिए ज्यादातियां हुने थीं तथा कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हुआ था। इन सूचनाओं का इतना राजनीतिक प्रभाव

तो हुआ ही था कि 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आईं तो उन्होंने आबादी नियंत्रण कार्यक्रम को सरकारी सूची से अपोषित रूप से लगभग हटा दिया था तथा जनता पार्टी की सरकार जिसमें तत्कालीन जनसंख्या और पृष्ठभूमि में आरएसएस शामिल थी, ने अपनी पूर्व भूमिका को कुछ बदला तथा परिवार नियोजन पर मौन साध लिया। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति का आबादी संबंधी संवाद लगभग 1980 से लेकर 2000 तक बिल्कुल ही मुख्य संवाद के मुहों से हट गया। स्वर्गीय सुदर्शन जी के प्रभाव में यह भी हुआ कि जब मध्य प्रदेश में 2003 में भाजपा सरकार बनी और उस सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बने तो उन्होंने श्री दिग्विजय सिंह की सरकार के द्वारा उठाए गए आबादी नियंत्रण के एक तार्किक और वैधानिक कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया। भले ही देश में आज श्री दिग्विजय सिंह की छवि मुस्लिम परसे बनाई गई हो परंतु मैं आज भी उनको इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपनी सरकार में स्थानीय संस्थाओं के लिए यह नियम बनाया था कि पंच, सरपंच आदि का चुनाव वही लोग लड़ सकेंगे जिनके अधिकतम दो बच्चे हो। उन्होंने इस कानून को विधानसभा से पारित भी कराया था और इस कानून को धर्म जाति या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रखा था। उस समय विधानसभा में भाजपा ने इसका इसका समर्थन किया था और उसी भाजपा ने पूर्ण यू टर्न लेकर 2008 के बाद उसे समाप्त कर दिया था। भाजपा को भी नीतियों के मामले में अपनी तत्कालीन राजनीतिक जरूरतों के आधार पर उलट पलट करने का उन्मुख कौशल हासिल है।

अभी पिछले दिनों में इलाहाबाद में एक पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में गया था और वहां मैंने देश की आबादी वृद्धि की समस्या के प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित किया था। मेरे एक बुद्धिजीवी मित्र जो की एक प्रोफेसर रहे हैं ने मुझे टोकते हुए हस्तक्षेप किया कि देश में आबादी की वृद्धि की दर उनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्थिर हो चुकी है और आबादी वृद्धि अब कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं उनके इस ज्ञान से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने दिनान्दिन जीवन और देश को जिस रूप में देख रहा हूँ उसमें मुझे आबादी वृद्धि तो दूर आबादी वृद्धि का विस्फोट नजर आता है। दुनिया के वैश्विक अध्ययन संस्थानों में आमतौर पर कॉरपोरेट फंडिंग होती है और वे अपने आप को एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन कहते हैं ने अब एक नई चर्चा शुरू की है जो आबादी की वृद्धि के लिए तर्क के पैर देती है। देश की सार्वजनिक स्मृति अक्सर कमजोर होती है और वह घटनाओं या सूचनाओं के मीडिया के मुख्य पृष्ठ या मुख्य खबर से टटते ही भी-धरे अपने आप भुला दी जाती है। 2009 के आसपास जब स्वर्गीय एपिजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे तथा प्रतिष्ठानों के केंद्र से यह चर्चा शुरू हुई थी कि भारत अब युवकों का देश बन गया है और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है न केवल तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बल्कि लगभग सभी दलों के राजनेता मुझ जैसे को छोड़कर इस पर गौरवान्वित होते थे कि देश की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि देश युवाओं का देश है। हालांकि मैं लगातार कहता और बोलता रहा कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो यह भी संकेत देती है कि 85 से 90 के बाद देश की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर वह प्रसन्नता का कारण सही भी है तब भी दूसरे पक्ष महत्वपूर्ण हैं। तथ्य यह है

कि अधिकांश युवा बेरोजगार हैं या अर्ध रोजगार में हैं। युवकों का एक बड़ा हिस्सा अपराधों में लिप्त है और संस्कार तथा मूल्य विहीनता में जी रहा है। एक अच्छी खासी युवा आबादी नशे में डूबी है इसलिए युवाओं की संख्या गौरव की बात नहीं है बल्कि देश में एक ऐसे युवाओं की संख्या हो जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, देश और समाज के प्रति समर्पित हो, जीवन मूल्यों के प्रति संकल्पित हो, वह गौरव की बात हो सकती है। जिन वैश्विक शोध संस्थानों ने यह आंकड़े देकर उस समय देश को युवा आबादी का देश बनने का उत्सव मनवाया था अब वही कुछ दिनों से कह रहे हैं कि भारत बूढ़ा हो रहा है और युवा आबादी घट रही है। भारत सरकार ने यूथ इंडिया 2022 की रपट जारी की है कि देश की युवा आबादी जो अभी 47 प्रतिशत है वह घटकर 2036 तक 34.55 करोड़ हो जाएगी। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं और आगे 15 वर्षों में यह संख्या और कम होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनपीएफ की इंडिया एंजिंग रिपोर्ट 2023, के अनुसार 2011 में भारत की युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी जो अब बढ़कर 2023 में 29 साल हो गई है यानी बुजुर्गों की संख्या 2050 तक बढ़कर लगभग कुल आबादी की 20 प्रतिशत हो जाएगी। यूथ इंडिया भारत सरकार की रपट में यह भी कहा गया की 2011 में प्रजनन दर 2.4 प्रतिशत थी जो अब घटकर दो प्रतिशत हो गई है तथा मृत्यु दर जो 2011 में प्रति हजार 7.1 थी वह 2019 में घटकर 6 हो गई है। संभवत 2024 में यह घटकर चार या पांच के बीच हो जाएगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू बुजुर्ग आबादी को लेकर बहुत चिंतित हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए कहा कि लोग कम से कम दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करें, हम ऐसे दंपतियों को प्रोत्साहित करेंगे। राज्य सरकार शीघ्र ही ऐसा कानून लाएगी की दो या उससे अधिक बच्चे वाले ही चुनाव लड़ सकें। नायडू के इस बयान ने जहां एक तरफ पहले अधिकतम दो बच्चों की धारणा थी के स्थान पर अब न्यूनतम दो की नीति को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 1950 के दशक में देश की आबादी की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत थी जो 2024 में घटकर 1 प्रतिशत हो गई है। नायडू के बारे में मेरी समझ पहले भी थी और आज भी है कि वह अमेरिका व पूंजीवादी दुनिया के आर्थिक एजेंट को लागू करने वाले सीईओ जैसे हैं, उसका प्रमाण तब भी मिला था जब देवगोडा देश के प्रधानमंत्री थे तथा नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। देश के प्रधानमंत्री ने एक राजनयिक शिफ्टाचार के तहत उन्हें शाम को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया था पर उन्होंने उसे स्वीकार न कर पहले हैदराबाद जाकर चंद्रबाबू नायडू का निमंत्रण स्वीकार किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि नायडू दुनिया के कारपोरेट और कॉर्पोरेट सरकारों के सितारे रहे हैं। स्वाभाविक है कि वैश्विक दुनिया के अपने उद्देश्यों के लिए जारी किए गए आंकड़ों में उनका विश्वास कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने बताया कि 1950 में जनसंख्या की वृद्धि दर 6 प्रतिशत थी यानी मान लो कि 1950 में देश की आबादी 36 करोड़ थी तो उसका 6 प्रतिशत लगभग 2.16 करोड़ हुआ। 1950 में मृत्यु दर प्रति हजार 12 थी यानी लगभग 44 लाख लोग देश में मृत्यु के शिकार होते थे। आबादी वृद्धि में से मौतों की संख्या को घटकर याने जीवित आबादी वृद्धि बची लगभग

1.70 करोड़ और अगर उनका ही आंकड़ा माने तो अब प्रतिवर्ष की दर एक प्रतिशत, माने लगभग 1.5 करोड़ लोग और मृत्यु दर घट कर रह गई हजार पर छह की संख्या में। याने देश में मरने वालों की संख्या अब घटकर एक करोड़ प्रतिवर्ष। आबादी की वृद्धि संख्या और मृत्यु में कमी के बाद लगभग 2 करोड़ के आसपास नई आबादी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आबादी पहले भी लगभग दो करोड़ प्रतिवर्ष के आसपास बढ़ रही थी अभी भी लगभग उतनी ही बढ़ रही है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। कुल मिलाकर देश में औसत आबादी की वृद्धि प्रतिशत में भले ही कम हुई हो पर वास्तविक रूप में वह आज भी दो करोड़ के आसपास है याने लगभग यथावत है। दूसरा पक्ष यह भी है कि आंध्र प्रदेश अब विभाजित है उसका एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना के रूप में नए प्रदेश में चला गया। इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू का आबादी का आंकड़ा कुछ गड़बड़ आया हुआ लगता है। तीसरा पक्ष है कि चंद्रबाबू नायडू ज्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय मृत्यु दर कम करने के प्रयास अपनी सरकार के माध्यम से करें तो यह विस्मयित दूर होने लगेंगे।

उन्हें वृद्धों की आबादी से भय है जोकि बहुत तार्किक नहीं है एक तो इसलिए कि आज मशीनीकरण और वैश्वीकरण के चलते एक-एक मशीन से कई हजार मजदूरों का काम हो रहा है इसलिए वैसे ही युवकों के लिए रोजगार की संख्या काफी कम हो रही है और अगर युवकों की संख्या बढ़ जाए और वे केवल बेरोजगारी, भुखमरी, आत्महत्या या अपराधी होकर मरें तो ऐसी आबादी का भी कोई भला नहीं होगा। श्री नायडू को चाहिए कि वह अपने प्रदेश के किसानों की आत्महत्याओं को रोके, बेरोजगारों की आत्महत्याओं को रोके और जिंदा युवकों को बचाने का प्रयास करें।

विदेशी यूएनओ और एनजीओ के आंकड़ों के पीछे कई छिपे हुए वैश्विक हित होते हैं। वैश्विक पूंजीवाद निरंतर उन्नत और अति समर्थ तकनीक को ओर बढ़ रहा है। पहले यानी 18वीं सदी के पूंजीवाद में, एक मजदूर अपनी तालत भर कमाकर, पूंजी के मालिक को देता था, जिसका कुछ हिस्सा उसे जिंदा रहने के लिए मजदूरी के रूप में वापस दिया जाता था ताकि वह जिंदा बना रहे और निरंतर काम करता रहे। वह इतना मजबूत भी नहीं हो कि काम न करे, यानि इतना कमजोर भी न रहे की काम करने के लायक भी न रहे। पर अब पूंजीवाद का नया स्वरूप उससे भी भयावह है। अब उसे केवल, उन्नत तकनीक चाहिए जो हजारों लाखों का काम अकेले एक बटन से कर सके। पर रंगीन या गरीब दुनिया में, उसे खरीददार भी चाहिए, वरना बिपुल पैदावार का क्या होगा ? तो अब उसे, भारत, अफ्रीका जैसे देशों में खरीददारों की संख्या बढ़ाना है, तो फिर आबादी वृद्धि जरूरी है। शायद वृद्धों के बढ़ने का व जवानों के घटने का शोर इस रणनीति को क्रियान्वित करने का एक हिस्सा है। रूस में यह ठीक हो सकता है क्योंकि बर्फीले प्रदेशों में प्राकृतिक रूप में जन्म दर बहुत कम रहती है। वैसे भी यूरोप अमेरिका में प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल भारत की तुलना में ज्यादा है। आशा है देश में केंद्र की सरकार व सुबाई सरकारें इस षडयंत्र को समझेंगी। जमीनी हकीकत यह है कि 1950 में आबादी का विस्फोट है और वह भयावह दृश्य पैदा कर रहा है। सरकार को जमीनी सत्य के आधार पर आबादी नियंत्रण नीति बनानी चाहिए जो धर्म जाति के आधार पर नहीं वरन सभी को साथ लेकर बने।

(जगत फीचर्स)

कलम के सिपाही...

निर्भीक और साहसिक
पत्रकारिता के खास
पहचान रखते हैं आशुतोष

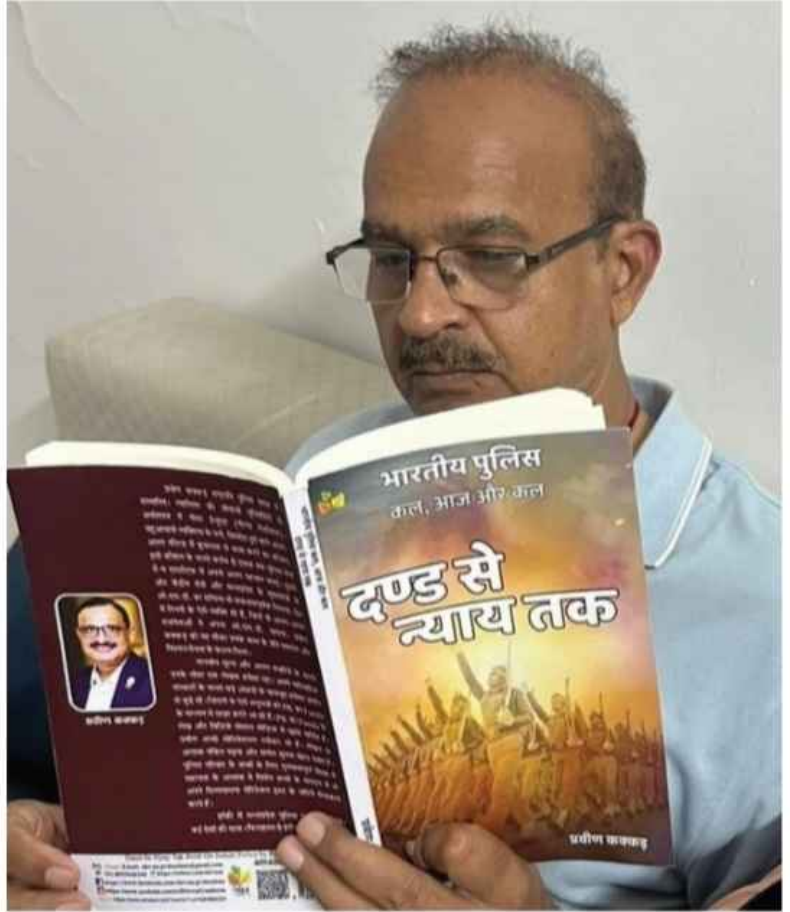


आशुतोष चतुर्वेदी अपनी निर्भीक और साहसिक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आशुतोष चतुर्वेदी आजतक के साथ बत्तीर एंकर और एसोसिएट एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। करीब 15 साल की अपनी पत्रकारिता में राजनीति से लेकर सभा और खेल के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में रिपोर्टिंग के जरिए दर्शकों से जुड़े रहे। फ्रीलैंड से लाइव एंकिंग और रिपोर्टिंग आशुतोष की विशेषता है।

आशुतोष मूल रूप से बलिया, उत्तर प्रदेश भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने ईंग्लैंड की कॉलेज, इलाहाबाद से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, और उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, नोएडा भारत से मास्टर पत्रकारिता पाठ्यक्रम पूरा किया है। उन्हें गायन बहुत पसंद है और उन्होंने गायन के लिए अपने कॉलेज में 'ईंग्लैंड आइडल' का खिताब भी जीता था। 2006 में सोनी टीवी पर प्रसारित इंडियन आइडल के सिंगिंग शो में वह शीर्ष 60 प्रतिभागियों में शामिल थे। आशुतोष ने मीडिया में अपना करियर एक फ्रीट पत्रकार के रूप में शुरू किया, अमर उजाला जैसे स्थानीय और हिंदी समाचार आउटलेट के लिए काम किया। इस दौरान, संपादक उदय सिन्हा ने उनका मार्गदर्शन किया और टेलीविजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अपने वर्तमान करियर में स्थापित होने से पहले आशुतोष ने जी स्पोर्ट्स, आवाज न्यूज और खबर भारती में काम किया। अपनी यात्रा के दौरान, आशुतोष ने उद्योग में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया और काम का एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो बनाया। अब उन्हें व्यवसाय में सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक के रूप में जाना जाता है। आशुतोष को दर्शकों को सटीक जानकारी प्रदान करने का शौक है और वह निष्पक्षता के साथ कहानियों को निष्पक्ष रूप से पेश करने का प्रयास करते हैं। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें भारत और विदेशों में पहचान दिलाई है। डिबेट हो या बड़ी घटना, फटनास्थल पर पहुंचकर वहां से सजीब वितरण इनका मजबूत पक्ष है। कई मौकों पर पाकिस्तान बॉर्डर से रिपोर्टिंग, कश्मीर में सीआरपीएफ पर स्पेशल कवरेज के लिए सीआरपीएफ की ओर से आशुतोष को सम्मानित किया जा चुका है। फ्रीट मीडिया से अपनी पत्रकारिता शुरू करने वाले आशुतोष एक मेहनती युवा टीवी पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।

सुधार के लिए प्रवर्तन: भारत की विकसित आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी की यात्रा” -आईपीएस शैलेंद्र श्रीवास्तव, रिटायर्ड डीजी

“दण्ड से न्याय तक” एक पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ की एक आकर्षक कहानी है, जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक नेताओं सहित शीर्ष नीति निर्माताओं के प्रमुख सलाहकार के रूप में परिवर्तित हो गया। लेखक को एक बेहद पेशेवर अधिकारी के रूप में दो दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है, जो अपने हर भूमिका में दृढ़ दृष्टिकोण और प्रभावशीलता के लिए जाने जाते हैं। एक समस्या-समाधानकर्ता और अंडरवर्ल्ड और संगठित अपराध के खिलाफ एक मजबूत ताकत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा विशेष रूप से स्पेशल टास्क फोर्स के साथ उनके समय के दौरान मजबूत हुई थी। पुस्तक को चार अंतर्दृष्टिपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में भारत में कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन शोध किया गया है। पहले खंड में भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने औपनिवेशिक कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता की पड़ताल की गई है, जिसमें उन्हें नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता के साथ जोड़ा गया है। लेखक पुरानी व्यवस्था की कमियों, नए कानून के पीछे के तर्क और इसे आकार देने वाली जनमत इकट्ठा करने की समावेशी प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक रूपरेखा तैयार करता है। दूसरे भाग में, वे पुलिस सुधारों को संबोधित करते हैं, पुलिस बल में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और पुलिसिंग के भीतर विभिन्न पेशेवर दुविधाओं का सामना करते हैं। यह खंड प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डालने



वाले प्रणालीगत मुद्दों पर एक स्पष्ट नजर डालता है और अधिक न्यायसंगत और कुशल पुलिस सेवा बनाने के लिए सुधारों की मांग करता है। पुस्तक का तीसरा भाग न केवल भारत में, बल्कि विकसित और विकासशील दोनों देशों के साथ तुलना के माध्यम से पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटता है। यह विश्लेषण एक वैश्विक परिप्रेष्य प्रदान करता है कि राजनीतिक प्रभाव कानून प्रवर्तन प्रथाओं को कैसे आकार देते हैं, जो उन लोगों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो पुलिसिंग पर शासन के व्यापक

प्रभावों को समझना चाहते हैं। अंतिम भाग देशभक्ति और सार्वजनिक सेवा पर आधारित है, जिसमें विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसका समापन दुनियाभर की समकालीन पुलिसिंग प्रथाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की चर्चा के रूप में होता है, जिसमें इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से सबक लिया जाता है। “दण्ड से न्याय तक” एक संस्मरण से बड़कर है—यह एक विचारोत्तेजक पठन है जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर

एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। कानून प्रवर्तन और कानूनी सुधारों के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के इच्छुक पुलिस अकादमियों, कानून के छात्रों और पेशेवरों के लिए इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। एक समर्पित पुलिस अधिकारी और शीर्ष कानून निर्माताओं के भरोसेमंद विश्वासपात्र के रूप में लेखक का अनेखा लाभ इस पुस्तक को एक अमूल्य संसाधन बनाता है, जो लोकतांत्रिक समाज में पुलिसिंग की जटिलताओं और बारीकियों पर प्रकाश डालता है। (जगत फीचर्स)